1.01 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

—— —

2.02 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.15 म० प० पर पुन: समवेत हुई।
[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव [—जारी]

[हिन्दी]

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने इस बहस में जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। अगर उन्होंने कोई तीखी बात भी कही है तो मैं समझता हूं कि विचारों को तराशने के लिए किया है और तराशने पर कुछ चमक आ जाती है अगर उसमें कुछ तथ्य हों। एक बात, माननीय गाडगिल साहब हैं नहीं आज यहां।

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : हम आपकी बात उनको बता देंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब सुनने में भी बिचौलिये होने लगे हैं मान्यवर (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपट्नम) : यह बहुत दुर्भाग्य की बात है···यह असंसदीय है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : बिचौलिया असंसदीय शब्द नहीं है··· (व्यवधान)

श्री के० एस० राव : कृपया उस वक्तव्य को वापिस लीजिए।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं पूरा विश्वास करता हूं कि···

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : कृपया उस वक्तव्य को वापिस लीजिए। हम बिचौलिये नहीं हैं। हम सांसद हैं···(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हम सांसद हैं। हम बिचौलिये नहीं हैं ··(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : माननीय प्रधानमन्त्री जी को हमें संबोधित किए गए बिचौलिया शब्द को वापिस लेना चाहिए। (व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : जी नहीं, उन्होंने आपको ऐसा नहीं कहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, मैं इतना ही कह रहा था कि मैं एक बात कह रहा हूं, गाडगिल जी यहां हैं नहीं, उनको मैं अपनी बात सुनाना चाहता हूं, लेकिन वे हैं नहीं, तो मेरी बात को उनके पास तक पहुंचाने की बड़ी कृपा की। इन्होंने कहा कि मैं पहुंचा दूंगा, तो हमारे और गाडगिल जी के बीच में··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : प्रधानमंत्री जी में शालीनता होनी चाहिए, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। इससे सभा की गरिमा में वृद्धि नहीं होती ? इनकी ओर से यह कहना उचित नहीं है··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम बिलौलिये नहीं हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा है ?

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) उन्होंने बिचौलिया शब्द का इस्तेमाल किया है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या 'बिचौलिया' शब्द असंसदीय है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, क्या बिचौलिया असंसदीय है ? (व्यवधान) मान्यवर आप जो आदेश दें, अगर बिचौलिया असंसदीय है, तो मैं नहीं बोलूंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मेरे विचार से प्रधानमंत्री जी ने इसे ऐसे ही कहा है इसमें कुछ असंसदीय नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं खड़ा हूं। आपको बैठ जाना चाहिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रधानमंत्री जी ने इसे इस नजरिये से नहीं कहा है, उन्होंने

वास्तव में कुछ भी असंसदीय नहीं कहा है। मैं सहमत हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है।

अब प्रधानमंत्री जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप में विनोदवृत्ति होनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब राजीव जी आ गये हैं···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वे चुनाव हार गये हैं और उन्होंने विनोदवृत्ति भी खो दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताइये कि उन्होंने कौन से असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जब बोलना शुरू किया ता दो शब्द कहने के बाद आपकी उपस्थिति में इन्होंने कहा कि औपोजीशन के लीडर हाउस में नहीं हैं, वे होते तो मैं उनको सुनाता। हमने उनको अर्ज किया कि हो सकता है वे आने वाले होंगे, अगर नहीं हैं तो आपकी बात जो बोल रहे हैं, हम नोट करेंगे और अपने नेता को बता देंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, अब मैंने श्री भजन लाल को बोलने की अनुमति दी है तो आप क्यों खड़े हुए हैं ?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उनकी पार्टी में कोई बिचौलिया नहीं है उनके यहां एक नेता और बाकी कार्यकर्ता हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : यह सारे हाउस की इनसल्ट है, सब मैम्बरों की इनसल्ट है, हम प्रधानमंत्री जी का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। हम यही बात कहना चाहते हैं कि इन्होंने हाउस की इनसल्ट की है, इसलिए मेहरबानी करके अपने शब्द वापिस लें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने भजन लाल जी को सुन लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि वे अपना भाषण जारी रखें।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मेरा यह कहना है कि जो कमीशन ली है वह वापिस कर दें।

अध्यक्ष महोदय : कमीशन का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विपक्ष के नेता यहां उपस्थित नहीं हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : उन्होंने हमें बिचौलिये कहा है (व्यवधान) मैं यह बात मानता हूं कि उन्होंने इसे हल्के-फुल्के ढंग से कहा है—अब मैं अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री जी को उस वक्तव्य को वापिस लेना चाहिए क्योंकि इससे हमारी बेइज्जती हो रही है।

इसका अर्थ है, उन्होंने कहा है और वह स्वयं इसका समर्थन करना चाहते हैं कि वह असंसदीय नहीं है और 'बिचौलिया' एक संसदीय शब्द है। इसी तरह लगता है। तेलगू में जब हम पूछते हैं आपके पिता कैसे हैं, और इसके स्थान पर अगर हम कहें आपकी मां के पति कैसे हैं—'अम्मा मोगुडू' तो कैसा लगता है।

अगर वह संसद सदस्यों का सम्मान करते हैं तो उन्हें कहने दीजिए कि उन्होंने यह शब्द नहीं कहा है या उन्हें कहने दीजिए कि उन्हें यह पता करने के बजाय यह शब्द संसदीय है या असंसदीय, उन्हें अपना शब्द वापिस लेना चाहिए। इससे सभी सांसदों की बेइज्जती होती है। जब तक वह यह नहीं कहेंगे हम आगे सभा की कार्यवाही शुरू नहीं करेंगे। इससे प्रत्येक सांसद की बेइज्जती हो रही है या तो उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए या उन्हें कहना चाहिए कि वह यह शब्द वापिस लेते हैं दोनों में से एक उन्हें करना चाहिए। चाहे यह संसदीय है या असंसदीय वह यह नहीं कह सकते। महोदय, यह क्या··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चिदम्बरम।

श्री पी० चिदम्बरम : मेरा यह निवेदन है। यह गम्भीर वाद-विवाद··· (व्यवधान)

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : महोदय, समूचा सदन विपक्ष के नेता से आपके माध्यम से अपील करता है कि अपने सदस्यों पर नियन्त्रण करें हम सभा की कार्यवाही जारी रखना चाहते हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं श्री चिदम्बरम।

श्री पी० चिदम्बरम : मेरा यह निवेदन है। यह गम्भीर वाद-विवाद है। प्रधानमंत्री जी एक बहुत गम्भीर वाद-विवाद का उत्तर दे रहे थे और हमें यह आशा है कि वह निश्चय ही अपने उत्तर ध्यान से देंगे। महोदय मैंने अनुवाद में सुना है उन्होंने हिन्दी का शब्द 'बिचौलिया' इस्तैमाल किया है। जिसका अर्थ मिडलमेन (बिचौलिया) होता है। महोदय, आपने कहा है—प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं

कहा है—प्रधानमंत्री जी ने इसे ऐसे ही हल्के-फुल्के ढंग से कह दिया है। हम नाराज हैं अगर सांसद नाराज हैं तो यह कहने में क्या परेशानी है कि "अगर आप नाराज हैं, तो मैं अपना शब्द वापिस लेता हूं"...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से बिचौलिया शब्द असंसदीय नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि—अगर इस शब्द का इस्तेमाल करने से विपक्ष के लोगों को ठेस पहुंची है—कोई अन्य शब्द इस्तेमाल कर लीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके आदेशों का पूरा समर्थन करता हूं और एक शायद अनुवाद में कुछ गड़बड़ हो रहा हो। एक तो मैंने — (व्यवधान) —

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करें जिससे किसी को तकलीफ न हो।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, कतई नहीं होगी। मान्यवर, मैंने विरोधी दल के नेता के बारे में नहीं कहा था, मैंने तो गाड़गिल जी के बारे में कहा था। वह यहां नहीं है क्योंकि उन्होंने डिबेट में काफी विस्तार से शिरकत की थी। मैंने एक तो गाड़गिल जी के बारे में कहा था कि वह यहां नहीं हैं। भजन लाल जी या आप लोगों ने कहा कि आप जो बात कहेंगे, उसे उन तक पहुंचा देंगे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि मैं अपनी बात गाड़गिल जी के पास पहुंचाना चाहता हूं। वह यहां नहीं हैं। आपने कृपा की कि मेरी बात वहां तक पहुंचा देंगे। मेरे और गाड़गिल जी के बीच में आप हैं इसलिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं—(व्यवधान)—

अध्यक्ष महोदय : बैठ जायें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी, बोलने के लिए।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, सदन में तो हम लोग आपके माध्यम के द्वारा बात बताते हैं, इतने गौरव के स्थान पर आपके माध्यम के द्वारा बात बताते है...

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : हम प्रधान मंत्री जी को माननीय अध्यक्ष के द्वारा जरूर बात पहुंचायेंगे लेकिन माननीय अध्यक्ष के लिए बिचौलिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने बिचौलिया शब्द का इस्तेमाल किया है, वह अपने सम्मान के अनुकूल नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री भजन लाल : वे कहें कि मैंने ऐसा कहा नहीं है तो बात समझ में आती है या शब्द को वापस लें। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब अध्यक्ष जी का आदेश हो गया। आगे चलें, ऐसी क्या बात है। अध्यक्ष जी की तो मानिए।

और गाडगिल जी ने कहा कि, खासकर मेरा हवाला देते हुए कहा, बहुत कमजोर हैं, मान्यवर, मैं मानता हूं कि मैं एक अदना आदमी बहुत कमजोर हूं लेकिन इसी अदना आदमी से, कमजोर आदमी से साढ़े तीन साल तक सारे जोर से लड़ते रहे और उसका नतीजा तीन साल के इस कमजोर आदमी की लड़ाई से है कि हमारे साथी इधर हैं, आप उधर हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरी कमजोरी से भी थोड़ी सीख लीजिए और मेरी कमजोरी भी कोई कम कमजोर नहीं है और आप तो मजबूत रहे हैं इसलिए

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

मजबूती से उधर रहियेगा और किसी के भी सुनने की कमजोरी कभी जाहिर मत कीजिएगा, नहीं कहीं इधर न चले आयें और अगर न समझ में आवे तो घर जाकर समझिएगा और अगर समझ में कमी है तो मैं क्या ऊपर वाला भी मदद नहीं कर सकता। फिर कहा गया कि हम लोग, खासकर मेरे लिए, लोग नहीं, कि अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, इनडिसीजन, पहले तो कहा कन्फ्यूज्ड रहते हैं।

[अनुवाद]

लेकिन मेरी असमंजस की स्थिति के कारण आप भी चक्कर में पड़ गये हैं। अतः मेरी असमंजसता से सावधान रहें। इस प्रकार मेरी असमंजसता की स्थिति को कम न आंकें।

[हिन्दी]

फिर कहा गया कि अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं और उस अनिर्णय का परिणाम यह है कि लोक पाल का बिल, जिसका तीन साल से आप फैसला नहीं कर पाये, उसको पहली ही बार में हम लोग ले आये। अनिर्णय का नतीजा है कि पोस्टल बिल, जो वर्षों तक त्रिशंकु की तरह टंगा रहा, उसको हम लोग वापस ले आये। अनिर्णय का नतीजा यह है कि टी० वी० और रेडियो को स्वायत्तता देने की हम लोगों ने घोषणा की थी और उसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया। अनिर्णय का परिणाम यह है कि 59वां संविधान संशोधन जो आपने बहुत जोर से निर्णय किया था, उसको आपके ही सहयोग से, प्यार से, संशोधन करवा लिया।

एक माननीय सदस्य : मजबूरी से।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम तो आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि संशोधन आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। जहां आपका आभार है, वहां पर आपका आभार प्रकट करेंगे। अनिर्णय का यह भी नतीजा है कि भोपाल की त्रासदी के अन्दर अन्तरिम रिलीफ की बात कही जा रही थी, उसका हम लोगों ने निर्णय लिया। अनिर्णय का यह भी नतीजा हम लोगों का है कि बोफोर्स के मामले में जो एफ० आई० आर० लॉज नहीं हो रही थी, जो खाते जब्त नहीं हो रहे थे, जो तीन साल में नहीं हो सके, हमने एफ० आई० आर० लॉज करके तीन दिन में जब्त कर लिए। अनिर्णय की यह भी स्थिति है हम लोगों की कि हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में इन्टरस्टेट काउन्सिल की घोषणा की और 90 दिन में उसको बना भी दिया। अनिर्णय की यह भी स्थिति है कि गांवों के नौजवान परीक्षा के लिए भटक रहे थे, उनकी उम्र 26 से 28 हम लोगों ने कर दी। हरीश रावत जी ने उसके लिए धन्यवाद दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना तो आप मानते हैं क्योंकि उनका डायरैक्ट सम्बन्ध आपसे है। इन नौजवानों से सीधा सम्बन्ध है, मैं जानता हूं··· (व्यवधान)···

श्री हरीश रावत : धन्यवाद का ही उल्लेख नहीं किया था, उसके साथ और भी जोड़ा था।··· (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अनिर्णय का नतीजा यह है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि नौ बौद्धों को अनुसूचित जनजाति की सुविधायें मिलें। वह अनिर्णय की वजह से हम लोगों ने निर्णय कर दिया। यही नहीं नेशनल इन्टीग्रेशन काउन्सिल भी इसी अनिर्णय के अन्दर बन गयी। बाछावत रिपोर्ट इंशोरेंस इन्क्वायरी के बारे में, वह भी अनिर्णय में बन गई। अब आगे की परीक्षा लें तो शर्त लगा लीजिए। एक्स सोलजर की भांति हम लोग कहें कि अनिर्णित रहेगा, या निर्णित रहेगा।

शर्त लगा लीजिए··· (व्यवधान)···वन-रैंक-वन-पैंशन-की बात हम लोगों ने कही है, हिम्मत है तो आप कह दीजिए कि आप लोग निर्णय नहीं करेंगे। खामोश हैं, मान्यवर···(व्यवधान)···परीक्षा करनी हो तो कह दीजिए कि कर्ज की माफी हम लोगों ने कही है, हम लोग अनिर्णय की स्थिति में हैं हम नहीं करेंगे, इसी बजट सत्र में। फिर कह दीजिए हम लोगों ने कहा है कि जो जमीन के कानून हैं उनको 9वें शैड्यूल में ले आयेंगे, हम लोग निर्णय नहीं करेंगे। शर्त लगा लीजिए। मजदूरों की भागीदारी के लिए भी हम लोगों ने कहा है और कहा है कि इसी वर्ष सीक्रेट-बैलेट-पेपर के माध्यम से हम लोग करेंगे, शर्त लगा लीजिए कि हम लोग निर्णय नहीं करेंगे। यही अनिर्णय की वजह थी कि रिजर्वेशन के लिए आन्दोलन चल रहे थे, हम लोग अनिर्णय की दिशा में डटे रहे, उसका रिजर्वेशन भी पास करा लिया आपके सहयोग से। उसके लिए भी आपको धन्यवाद, क्योंकि यह संविधान का संशोधन है। दूसरे अनिर्णय की परीक्षा करनी है, तो कर्ज-मुक्ति पर कर लीजिए। इसी बजट सत्र में कर लीजिए, कह दीजिए कि नहीं करेंगे। आगे अनिर्णय के लिए चुनौती देनी हो तो पंचायत राज के बारे में, विकेन्द्रीकरण के बारे में कर लें। शर्त लगा लीजिए कि हम लोग लाते हैं कि नहीं निश्चित रूप से, दृढ़ निश्चय के साथ। और भी अनिर्णय की परीक्षा करनी हो तो महिलाओं को फीसदी पंचायतों में 30 हिस्सेदारी देंगे, उस पर भी शर्त लगा लीजिए। और भी अनिर्णय की अगर बात करनी हो तो संविधान के अन्दर काम के अधिकार को लाने की बात है, उसकी भी परीक्षा करनी हो तो बता दीजिए। आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो वह लेंगे। और भी अनिर्णय की हमारी परीक्षा करनी हो तो कहिये। हम अपने संसाधनों का 50 फीसदी ग्रामीण-क्षेत्रों में अपने प्लांस में, आठवें प्लान के अन्दर लगायेंगे, उसकी भी परीक्षा कर लीजिये। आप सच क्यों नहीं बोलते हैं? आप कमजोरी और मजबूती की बात छोड़ दीजिये, निर्णय और अनिर्णय की बात मत कीजिये। सरकार ने घोषित किया है, अपना घोषणा-पत्र कि पहली जनवरी तक हम यह करेंगे, वह निश्चित है, पत्थर की तरह और उसी मजबूती की तरह उस पर हम चल रहे हैं। इसमें हम सहयोगी दलों का आभार प्रकट करते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० बागा रेड्डी (मेड़क) : अध्यक्ष महोदय··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात समाप्त होने पर आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दे दीजिए परमीशन।

श्री एम० बागा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने बहुत से सरकारी निर्णय जो लिए हैं उनके इम्पलीमेंटेशन के ताल्लुक से कहा। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा निर्णय यह लिया था, वह निर्णय आपके मेनिफेस्टों में भी लिखा गया है और उसका प्रचार भी किया गया कि दस हजार रुपये तक के कर्जे··· (व्यवधान) बड़े आश्चर्य की बात है कि जो बात कही गयी थी···आप लोग कहते हैं, आपके मुख्य मंत्री कहते हैं (व्यवधान) लेकिन इसमें उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्जे की माफी पर भी शर्त लगा ली जाये कि यह इस बजट सेशन में आता है या नहीं आता है।

इसमें मैं विशेष रूप से अपने सहयोगी दलों का आभार प्रकट करना चाहता हूं···

श्री मदन लाल खुराना : दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की बात भी कह दीजिए कि वह भी ला रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मण्डल आयोग की बात भी कह दीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मंडल आयोग की बात आगे आयेगी। आप चिन्ता मत कीजिए, कुछ छूटेगा नहीं।

मैं अपने सहयोगी दलों का इसलिए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक नयी परम्परा डल रही है। इसलिए नहीं कि सत्ता में इस सरकार को कायम रखना है। यह मकसद नहीं है। लेकिन मुद्दों के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर एक राजनीति की परम्परा डालने के इस योगदान में, इस महा-युद्ध में जो भी साथी दल हैं, उनका एक बड़ा ऐतिहासिक योगदान मैं मानता हूं। क्योंकि व्यक्ति आधारित राजनीति से हटकर, मुद्दों पर आधारित राजनीति का प्रादुर्भाव हो रहा है विचारहीन एकात्मकता के मुकाबले में, मैं समझता हूं कि विचारशील द्वंद्व जनतन्त्र में भला है।

हम लोगों के कुछ मुद्दों में अन्तर है। हम उनको छिपाते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। लेकिन तमाम राष्ट्रीय मुद्दे जो ऐसे हैं जिन पर एकता हो सकती है उनमें एकता लाने की परम्परा हम डालना चाहते हैं। इसमें हमें आपका भी सहयोग मिला है, ठीक है। आपका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि राष्ट्रीय हैं जिनमें आपने योगदान दिया। 59वां संशोधन आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता था। रिजर्वेशन के मामले में भी आपने सहयोग दिया। कश्मीर के मामले में आपने सहयोग दिया। तो एक परम्परा आदान-प्रदान की, एक-दूसरे के आदर-भाव से, थोड़ा हंसी-मजाक से चलती है। एक राष्ट्रीय मुद्दों के अन्दर कांसेसस की राजनीति का प्रयास हो रहा है। मैं समझता हूं कि देश के मूल हितों की रक्षा के लिए यह एक स्वस्थ परम्परा पड़ रही है। यह आरोप भी हम लोगों पर लगाया जाता था कि यह अवसरवादी गठबंधन है, लेकिन आज हमारा कोई भी सहयोगी दल कुर्सी पर नहीं बैठा है, न वामपंथी दल और न भारतीय जनता पार्टी, दोनों कुर्सी की वजह से समर्थन नहीं दे रहे हैं, कोई कुर्सी पर नहीं है, कोई अवसरवादी नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : वे और भी अधिकार प्राप्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : गंभीरता से बात सुनें, जो बात सत्य है उसको समझिये। तो यह कोई एक अवसरवादी गठबंधन नहीं है, बल्कि कार्यक्रमों के आधार पर, व्यक्तिवादी राजनीति से हटकर मुद्दों की राजनीति की परंपरा की ओर चल रहे हैं।

सोमनाथ चटर्जी जी ने कई चीजें मौजूदा सरकार के बारे में कहीं, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। गाडगिल जी ने प्लानिंग के बारे में एक मुद्दा उठाया, ग्रोथ रेट के बारे में उन्होंने कुछ चीजें कहीं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं इस सदन को कि विकास के प्रति सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है और जो विकास की गति रही है, उसको हम बढ़ाए रखना चाहते हैं, उसको कायम रखना चाहते हैं, लेकिन उस विकास के अन्दर हिस्सेदारी किसकी हो, इस पर जरूर हम निगाह रखना चाहते हैं और यही अन्तर है, केवल विकास के आंकड़े से हमको सन्तोष नहीं है। जो बेकारी है, उसको मुख्य मुद्दा मान कर, जो नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या है, हम आठवीं पंचवर्षीय योजना बनाना चाहते हैं, विकेन्द्रीकरण, जनता की भागीदारी, जनोन्मुखी हमारी नीतियां और जो फैडरल स्ट्रक्चर है, उसको और दृढ़ करने के लिए यह जरूरी है। केवल आंकड़ों के अन्दर हमारी

योजनाएं नहीं हैं, एक संख्या कभी विकास नहीं होती, वल्कि उसका स्वरूप क्या है, उस स्वरूप में जो कमियां रही हैं, उसमें हम सुधार लाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में जो कमियां हमारे विकास की रही हैं, मैं समझता हूं कि दो रही हैं, विकास की स्ट्रेटजी में। यद्यपि इधर जो आंकड़े में विकास आया है जब आप रहे हैं, अच्छा रहा है। संख्या में स्टेटिस्टीकली ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन एक बात कृषि में जितना विकास होना चाहिए था, जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। कृषि के अन्दर जो पूंजी लगनी चाहिए थी वह या तो स्थायी रही या कुछ कम होती चली गई। यह हमारी रणनीति में है, गरीबी दूर करने की रणनीति में बड़ी भारी कमियां थीं, दूसरा मैंने कहा कि बेकारी की समस्या पर सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ा हमारे विकास का और इस सिलसिले में आप अगर देखें तो यह ग्राफ है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सन् 1980 के बाद ग्रास कैपिटल फारमेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में है, वह स्थायी रही या नीचे रही, कुछ कम रही, यही होता रहा, उसकी हमको पकड़ करनी चाहिए। भारत वहां रहता है और इसको दूर करने के लिए प्लान एलोकेशन में फीसदी हम लोग 50 संसाधन गांवों में लगाना चाहते हैं।

केन्द्र का बजट मान लीजिए कुछ कम है डिफेंस का बहुत ज्यादा आता है, मगर प्लान में नैशनल रिसोर्सिज का कमिटमेंट स्टेट और सैंटर को मिलाकर 50 प्रतिशत कम से कम गांवों में लगे। इसी के साथ उद्योग के अन्दर कैपिटल इंटेंसिटी के उद्योग की बजाए लेबर इंटेंसिटी की ओर हम जाना चाहते हैं। कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं और लघु-उद्योग हैं, वे हमारी औद्योगिक नीति के प्रमुख अंग रहेंगे। क्योंकि उसी के माध्यम से गांव भी मजबूत बनेगा, हमारे उद्योग भी मजबूत बनेंगे और एक दूसरे के पोषक बनेंगे। हमारी कृषि पोषक होगी उद्योग की और उद्योग पोषक होंगे हमारी कृषि के। एक बात गौर करने की है कि जहां देश में इण्डस्ट्रीय पॉलिसी रैंज्योलूशन तो हुआ, इसे सदन में रखा गया और राष्ट्र को औद्योगिक दिशा देने में उसको ढांचा देने में उसने काफी प्रभावशाली रोल अदा किया है। क्या कारण है कि कोई एग्रीकल्चरल पॉलिसी रेज्योलूशन इस देश में नहीं हुआ आज तक। कृषि से सम्बन्धित हम लोग जितने आए हैं, अगर सोचें इस सदन के अन्दर, अधिकतर लोग होंगे जो गांव से होंगे, पॉलिसी स्टेटमेंट भले हुआ हो कृषि पर, लेकिन एक सरकार का स्टेटमेंट एक पॉलिसी रैंज्योलूशन का मुकाबला नहीं करता। क्योंकि नैशनल पॉलिसी रैंज्योलूशन कई सरकारों को बांधता है, चाहे वह सरकार आये या कोई और सरकार आये। ऐसे ही कृषि नीति का प्रस्ताव होना चाहिए, जिसे हम स्वीकार करें, चर्चा करें। जिसमें किसी प्रकार की, किसी मन्त्री की बात न हो, बल्कि उसका नाम भविष्य के परिपेक्ष्य में देखकर, एक राष्ट्रीय दिशा मान कर, गांवों की आवाज मान कर, खेत-खलिहान की आवाज मान कर राष्ट्रीय स्तर पर रखें। जो भी सरकार आए, लेकिन वह इस दिशा पर चले। ऐसी एक पॉलिसी बननी चाहिए। मैं समझता हूं एग्रीकल्चर पॉलिसी रैंज्योलूशन यहां पर आना चाहिए।

लेकिन अभी जो समस्याएं हम लोगों के सामने हैं-एक तो पब्लिक सैक्टर के योगदान की बात है। उसमें हम लोग मजदूरों की भागीदारी लेकर, उनको हिस्सेदार बना कर, हम समझते हैं केवल प्रबन्ध में भागीदार नहीं, बल्कि ऑनरशिप में मजदूरों की भागीदारी का सूत्रपात होना चाहिए। उसकी क्या रूप-रेखा हो, यह बहस की बात है, विचार की बात है। पब्लिक सैक्टर की जो गति है, मेरा विश्वास है कि मजदूरों को जब तक हम विश्वास में नहीं लेते, जब तक उनको भागीदार नहीं बनाते, खाली प्रबन्ध में नहीं, मिलकियत में भागीदार नहीं बनाते हैं, पब्लिक सैक्टर का रास्ता नहीं निकाल पाते हैं। इस दिशा में हम लोग इसी वर्ष में पब्लिक सैक्टर के लिए सिक्रेट बैलेट के माध्यम से रैंज्योलूशन ले आयेंगे। लेकिन यह जरूरी है कि पब्लिक सैक्टर में जितनी पूंजी लगी है, उसके मुकाबले में देश को पूंजी कमा कर के यह दे। यह अति आवश्यक है। पब्लिक सैक्टर पर एक श्वेत-पत्र हम

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

आयेंगे। इस समय जो हमारे सामने समस्या आयी हुई है वह अर्थव्यवस्था में दो दिशाओं में आयी हुई है। एक तो हमारा अन्दरूनी कर्ज है और एक विदेशी कर्ज। अभी तक इस पर कुछ मुंह ढांपा-ढांपी का ढंग चलता रहा कर्जा लेकर के। हमारी देशी मुद्रा के रिजर्व हैं उनको थोड़ा खर्च करके उस पर पर्दा पड़ा रहा। लेकिन अब वह पर्दा नहीं रह सकता। बेहतर है कि स्थिति को आपके, सदन के और देश के सामने रखा जाए और उसकी अहमियत को समझा जाए। डैट सर्विस अगर हम देखें पेमेंट जो हैं वह 1984-85 में दो हजार पांच सौ तेइस करोड़ थे जो 1988-89 में सात हजार छत्तीस करोड़ हो गये। एन० आर० आई० के जो डिपाजिट हैं उसकी डैट सर्विस न लें, उनकी अदायगी में पैसा जाता है तो मीडियम और लांग टर्म पर 24 फीसदी डैट सर्विस हो गई जो जोड़कर देखें तो करीब-करीब 30 फीसदी है। हम लोगों को जो धनराशि मिली शुरू के साल में सात हजार चालीस करोड़ विदेशी मुद्रा रिजर्व थी तो जब यह सरकार आई तो पांच हजार पांच सौ करोड़ रह गई, इसमें छीजन हुआ एक साल के अन्दर, इस सरकार के आने के पहले। विदेशी मुद्रा का जो रिजर्व कप था इसलिए कि दो महीने इम्पोर्ट में रह गये। मैं इसलिए सदन के सामने रखना चाहता हूं कि कठिन समस्याएं सरकार के सामने हैं वह आपको मालूम हों, लेकिन मैं पिछली सरकार की निन्दा नहीं करूंगा, वह छोड़ दीजिए। आगे आर्थिक आजादी कायम रखने के लिए हमें किसी के मातहत नहीं रहना है। हमें कहीं जाकर भिक्षा मांगकर अपनी आर्थिक आजादी को गिरवी नहीं रखना है। इसलिए कठिन निर्णय हमको करने होंगे। हमने उनकी मजबूरी देखी है जो बड़े-बड़े कर्जों के अन्दर पड़ जाते हैं। एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक मंत्री जो कि कर्ज में डूबे हुए देश का था, एक स्टेटमैंट देता है, ताज्जुब हुआ कि यह कैसे हिम्मत कर रहा है। सेशन 15 मिनट के लिए स्थगित हो जाता है और उसको कुछ कहा जाता है तो वही मंत्री 15 मिनट बाद उलट बात कहता है। इस गुलामी के दर्शन हमने देखे हैं और हमें इस गुलामी में नहीं जाना है। चाहे हमें अपना पेट काटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इसमें नहीं जाना है। यह सरकार अकेले इसको नहीं कर सकती है, यह जनता के बीच में जाकर कहना है कि हमको यह कदम इसलिए उठाने पड़ रहे हैं कि आर्थिक आजादी को कायम करने के लिए लड़ाई लड़नी है। अगर आप भीख मांग कर हाथ पसारेंगे तो भी आपको मजबूर होकर वे कदम उठाने पड़ेंगे कर्ज से निकलने के लिए। इस अर्थ में मैंने आपको इसके विश्वास में लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका समर्थन मिलेगा और आगे के कदमों में आपको सहयोग भी मिलेगा। मौजूदा सरकार अपना ढिंढोरा पीटने में विश्वास नहीं करती है, क्योंकि हम लोग सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं, हम जनता की ओर से सरकार में हैं। इसलिए सरकार का ढिंढोरा पीटें यह हमारा काम नहीं है। कम से कम मैं तो अपना काम नहीं समझता हूं। मैं तो यह समझता हूं कि जनता की ओर से सरकार पर अंकुश रखना मेरा काम है। जिस दिन हम केवल सरकार का ढिंढोरा पीटने लगेंगे तो हम सरकारी अफसर हो जायेंगे, जन-प्रतिनिधि नहीं रह पायेंगे। इसलिए अपनी कमियों को हम स्वीकार करेंगे। 100 दिन में यह नहीं कि हमसे कुछ गलतियां न हुई हों, हो सकती हैं कुछ बातें आपको अलग से बतायेंगे. लेकिन हम लोगों ने गवर्नेंस की बात कही। लगता है कि लोगों को जिस लायक हमने सोचा, उस लायक नहीं थे तो इसलिए उसको किसी भी सरकार को या प्रधानमंत्री को, मान्यवर आकाश में कभी मत बिठाइये और आकाश पर बैठाकर कह दिया कि अब तो देश उसी के साथ नत्थी हुआ तो फिर जब गिरता है तो देश भी धड़ाम से गिरता है। इसलिए हमको अपनी कमियों को सदन में कहने में दिक्कत नहीं हुई है क्योंकि उसी में हमारा सुधार भी हो सकता है लेकिन हां, जिस संघर्ष को लेकर के हम आये हैं, उस संघर्ष को यहां भी जारी रखेंगे और उस संघर्ष के प्रति वफादार रहेंगे। वही हमारी मर्यादा और मापदण्ड है।

भजन लाल जी ने पंचायती राज के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी कि सरकार इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाऊं भजन लाल जी कि विकेन्द्रीयकरण के बारे में हम लोग प्रतिबद्ध हैं और पंचायती राज का बिल हम लोग इसी वर्ष ले आएंगे। आपके सामने ले आएंगे। हमको विश्वास होता है चूंकि आपने चिन्ता व्यक्त की है, और आपका समर्थन मिलेगा, इस-लिए उसे पास करने में दिक्कत नहीं है। इन्द्रजीत जी ने एक चीज कही थी कि सभी सदस्यों को अपने असेट्स डिक्लेयर करने हैं।

श्री भजन लाल : मैंने महम के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चाहे महम हो, चाहे रायबरेली और चाहे अमेठी हो, कहीं भी हिंसा के हम लोग समर्थक नहीं हो सकते हैं।

और पहली बार किसी दल ने··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : मेहम के बारे मे आप क्या कहते हैं। आपके लोग अभी तक वहां हैं।

श्री वाई० एस० राजेश्वर रेड्डी (कुडप्पा) : क्या आप जानते हैं कि हरियाणा में क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे कहने तो दीजिए। मैं बताता हूं क्यों अमेठी छोड़ दिया। छोड़ दिया, माफ कर दिया। अब तो बैठ जाइए। अब खत्म हुई बात। मान्यवर, पहली बार एक राज-नैतिक दल ने स्वयं रीपोल के लिए स्वयं इलेक्शन कमीशन से मांग की है। अमेठी में भी यही मांग होती तो बहुत चीजें नहीं होतीं, सुधार होता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री भजन लाल : इन्होंने कहा लेकिन इलेक्शन तो काउंटरमाडेड कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : राकेश जी, आप बैठ जाएं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : भजन लाल जी, आप क्यों ज्यादा बात करते हैं, गढ़वाना में आप हमारे साथ ही थे तो चलिए साथ मिलकर अब रास्ता निकाला जाए। (व्यवधान)

इन्द्रजीत जी ने एक बात कही कि सभी सदस्यों को अपने असेट्स की, अपने धन की घोषणा करें। मैं समझता हूं उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया, जिससे एक स्वस्थ परम्परा पड़ेगी और इस पर सरकार सकारात्मक ढंग से जरूर विचार करेगी।

श्री आर० एन० राकेश (चेल) : आप अपनी सम्पत्ति तो पहले बतलाइये कितनी है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप तो हमारे घर के हैं, आपसे क्या छिपायेंगे। (व्यवधान)

यहां प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा जी ने एक चीज कही कि रोजमर्रा के काम के सिलसिले में हमारी कुछ गाइडलाइन्स होनी चाहिए, डिस्क्रीशनरी तरीके से हर चीज के निर्णय नहीं होने चाहिए। विजय कुमार जी, इस विषय में आपसे अवश्य आदान-प्रदान करूंगा, मैं भी इसका समर्थक हूं कि किसी

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

गाइडलाइन के आधार पर, किन्हीं परम्पराओं के आधार पर ही सारी चीजें हों। आपका स्वागत है, हमें आपसे विचार-विमर्श करने में कोई वैसी बात नहीं है, हम लोग सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

यहां राजदेव सिंह जी और हरीश रावत जी ने "वन रैंक वन पेंशन" की बात कही, इस सिलसिले में हम इसी सत्र में आपके सामने एक प्रस्ताव लाने वाले हैं, वह आपके सामने आएगा और मुझे विश्वास है कि आपका समर्थन हमें मिलेगा। लेकिन मैं भूतपूर्व सैनिकों को केवल वेतनभोगी या पेंशनभोगी ही नहीं मानता, और न इस सिद्धान्त का पक्षधर हूं। उसकी जो अन्तिम आहुति, आखिरी त्याग हो सकता था, उसका प्रण लेकर, देश की रक्षा के लिए वह खड़े रहे। आज यदि हम अपने भूतपूर्व सैनिकों को देखें, अपनी सेना को देखें तो देश की एकता के सवाल पर, चाहे वह केरल का हो, कश्मीर का हो, बंगाल का हो या राजस्थान का हो, चाहे वह तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, चाहे वह इसाई हो, मुसलमान हो, हिन्दू हो या सिक्ख हो, जब वह सेना की वर्दी पहन लेता है तो सब कुछ छोड़कर वह भारतीय होता है, और कुछ नहीं। इस सदन के माध्यम से मैं भूतपूर्व सैनिकों से अपील करना चाहूंगा कि आज जो चुनौती देश पर आई है, उसे वह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की भावना से देखें, केवल वेतनभोगी या पेंशनर होकर नहीं। वे एक नया नेतृत्व लेकर सामने आएं: यदि गांव-गांव में ऐसी शक्ति जागृत होगी तो वह देश को बचाने और देश को मजबूत बनाने में भारी सहायक सिद्ध होगी।

अब मैं रक्षा के सम्बन्ध में आपसे थोड़ा-सा कहना चाहता हूं। इसलिए कहना चाहता हूं कि इस बारे में भी कई बातें कही गई हैं। बहुत कहा गया है कि यह सरकार कमजोर है, लेकिन जब देश की सरहदों के बाहर से चुनौतियां आ रही थीं, उस समय देश को मजबूत करने के लिए क्या हो रहा था? वर्ष 1988-89 में हमारा डिफेंस के लिए रिवाइज्ड एस्टीमेट 13,200 करोड़ रुपये का था, जबकि एक्चुअल 13,340 करोड़ खर्च रहा। उसके मुकाबले, जहां एक्चुअल 13,341 करोड़ रुपया खर्च हुआ, वर्ष 1989-90 यानी चालू वर्ष में 13 हजार करोड़ रुपये आबंटित किये गये। नतीजा यह हुआ कि जब यह सरकार सत्ता में आई तो पहले सेशन में जनवरी माह में हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं था और इस सरकार को 500 करोड़ रु० का सप्लीमेंटरी बजट लेकर आना पड़ा। यह देश को मजबूत करने का ढंग नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उस सबकी बात यहां हो, यहां ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि पूरे विश्व में डिफेंस की बजाय, रक्षा के मामलों में खर्च करने की बजाय, विकास कार्यों में ज्यादा धन लगाया जाए, अपने देश में भी ऐसा ही होना चाहिए, परन्तु यथार्थ को देखते हुए, मैं नहीं समझता कि देश को मजबूत करने की तरफ से ध्यान हटे। आप फौरेन एक्सचेंज का एस्केलेशन देख लें, महंगाई का एस्केलेशन देख लें, तो एक्चुअल टर्म्स में यह घटोत्तरी ही हुई है जबकि हमारी सरहदों पर चुनौतियां लगातार बढ़ती गई हैं।

3.00 म० प०

मेरा ख्याल है कि इसको भी हमें सुधारना पड़ेगा, बोझ जरूर पड़ेगा, लेकिन इस बोझ को भी देश की रक्षा के लिए हमें सहन करना होगा।

3.00 म० प०

हाण्डू साहब ने जम्मू-कश्मीर के बारे में बात कही। इस पर काफी चर्चा भी हुई। फर्नाण्डीज जी श्रीनगर गए हुए हैं और इस सम्बन्ध में देखेंगे, वे फिर जम्मू रहेंगे, तीन-चार दिन उधर ही रहेंगे।

उसके बाद आल पार्टी मीटिंग, आप सबसे मिलकर हो रही है। स्थिति चिन्ताजनक है, ऐसी स्थिति में मैं यहां कोई ऐसा चित्र नहीं खींचना चाहता हूं जिससे स्थिति खराब हो। इसको हम सबको करना है। इसके लिए मैं नेता, विरोधी दल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सहयोगात्मक ढंग से योगदान दिया है।

पंजाब का मामला राजदेव जी ने उठाया था। पंजाब में इधर हत्याएं बढ़ी हैं, फिरौतियों की संख्या भी बढ़ी है। अबोहर के लोग मेरे पास आए थे और इस माने में जो 1988 के लैवल पर था, उस स्तर से इस समय वहां हिंसा की घटनाएं नुकसान पहुंचा रही है, यह चिन्ताजनक चीज है, इस पर हम दृढ़ता से काबू लाएंगे। किसी भी मासूम की जान नहीं जाने देंगे। उसके लिए जितनी भी शक्ति लगाने की हमें जरूरत होगी, हम लगाएंगे। उधर जो अन्याय की भावना का अंदाज था उसको भी दूर करने की हमने कोशिश की है। उनसठवें संविधान संशोधन की बात, सन् 198 के राइट्स की बात राजदेव जी ने उठाई थी। स्पेशल कोर्ट्स भी 90—100 दिनों के अन्दर बनाए गए। जो डेजर्टर्स हैं, उनको भी छोड़ा गया है। उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा गया है कि वे घूमते रहेंगे, बल्कि उनको नौकरी के साथ छोड़ा गया है। विधवाओं के लिए और भी कुछ देने का प्रस्ताव दिया गया है। उस पर दिल्ली से भी प्रस्ताव आ रहा है। उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन जब तक एक वातावरण नहीं बनता है, तब तक स्थिति नहीं सुधर सकती है। अभी सब दलों की एक बैठक हुई, बहुत अच्छा हुआ। पंजाब में गवर्नर को सलाह देने के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाने की हम लोगों ने स्वीकृति दी है। वहां पर शान्ति का वातावरण बनाने की बड़ी आवश्यकता है और मुझे खुशी है कि जो सर्वदलीय बैठक हुई, जिसके अन्दर सभी मुख्य पार्टियां थीं, लेकिन अकाली दल मान उसमें शरीक नहीं हुआ था, परन्तु भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनता दल, अकाली दल बरनाला, अकाली दल बादल, ये सब पार्टियां थीं। उन्होंने भी इस चीज को अहसास किया कि पहले कंजीनियल एटमॉस्फीयर पंजाब में बनाने के लिए सब से बड़ी आवश्यकता है। इसे हम मानते हैं।

राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मसले पर सबसे बात करके, सहयोग से, आपस में आदान-प्रदान करके, इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए इस बात से हम सहमत हैं। एक कमेटी भी इसके लिए बनाई गई, उसकी बैठक जल्दी ही होगी। पहले चुनावों की वजह से फिर जम्मू-कश्मीर की समस्या की वजह से कुछ विलम्ब हुआ है, लेकिन उसकी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। हम आशा करते हैं कि समझदारी के साथ, कोई रास्ता निकलेगा।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सन् 1984 के विक्टिम्स की विधवाओं को जो 400 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी, उसे एक हजार रुपया कर दिया गया है।

विदेश नीति के बारे में गाडगिल जी ने कहा कि यह सरकार बड़ी कमजोर है। छोटे-छोटे देश भी अब बोलने लगे हैं। श्रीलंका, नेपाल और बंगलादेश भी बोलने लगे हैं। इस बात पर ताज्जुब भी होता है, क्षोभ भी होता है। कम से कम विदेश नीति एक ऐसा एरिया है जिसके अन्दर दलगत रूप से नहीं होगा, यह राष्ट्र की नीति होती है, कोई मेरे दल की नहीं है, विदेश नीति किसी एक दल की सम्पत्ति नहीं होती है देश की होती है और यह हमारी आजादी की लड़ाई के दौर से गढ़ी गई, अजमाई गई और इसे हमने स्वीकारा है, केवल सरकार ने नहीं स्वीकारा है बल्कि देश ने स्वीकारा है, जनता ने स्वीकारा है। मैं आपको जवाहरलाल जी के शब्द कहता हूं। हमारी विदेश नीति को बनाने में, गढ़ने में उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं उनके शब्द आपके लिए पढ़ता हूं :

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

[अनुवाद]

हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रत्येक देश को अपनी समस्यायें स्वयं सुलझानी चाहिएं, अपना एक अस्तित्व कायम करना चाहिए। किसी देश द्वारा अन्य देशों को अपना उपनिवेश बनाने अथवा आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से उन पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में हम विश्वास नहीं करते।

[हिन्दी]

हमारी विदेश नीति का क्या आधार था? आधार था समानता का, आदर का, आधार था पंचशील का और हम यह कहें कि वह छोटा देश कैसे हमसे बोल रहा है। जिस नीति की नींव डाली गई, क्या उस पर कुठाराघात नहीं हो रहा है जब हम यह कहें कि छोटा देश नेपाल तुम क्या बोलते हो, श्रीलंका तुम क्या बोलते हो, कहां है हमारी यारी-दोस्ती। हम बड़े देशों का इसलिए मुकाबला कर सके हैं, सामने सिर ऊंचा करके क्योंकि हमने छोटे देशों को दबाने की नीति नहीं अपनाई है। अगर हम छोटों को ऐसे देखेंगे तो जब बड़े आएंगे तो हम घुटने टेकेंगे क्योंकि हमारी मानसिकता छोटे-बड़े की रहेगी। हमारी विदेश नीति की समानता हम आने नहीं देंगे। इस अर्थ में अगर आप देखें तो मालद्वीप के प्रैजीडैंट आए हुए हैं। पहले हैड आफ स्टेट सबसे छोटे देश के आए हैं। गनीमत है कि आप उस पर टिप्पणी नहीं करते कि क्या छोटे देश के प्रैजीडैन्ट आए हैं। हमारे ऐक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की पहली यात्रा भी मालद्वीप की थी। कहां छोटे देशों को जा रहे हैं, बड़े-बड़े देश जाना चाहिए। अब नामीबिया जा रहे हैं। यह न कहिएगा कि आबादी के हिसाब से क्या छोटा देश है, अफ्रीका जाइए। छोटा-बड़ा देश नहीं होता है, मूल्य छोटे बड़े होते हैं। हमारी विदेश नीति मूल्यों पर अंकित रही है, उसे मत बिगाड़िये, और देशों का आदर करें। आज पाकिस्तान ने इसलिए दखलअन्दाजी बढ़ा दी क्योंकि सरकार को कमजोर समझता है। इस दखलअन्दाजी की फरियाद तो आप भी करते रहे हैं, क्या कमजोर थे आप? सियाचिन की बात उठाई, क्या कमजोर थे आप, मैं तो नहीं कहता कमजोर थे। इस चीज की विकृति नहीं होनी चाहिए। नेपाल तो आपके समय में अकड़कर बोलता था, अब तो हमारी चीजों की, हमारी सिक्यूरिटी की बात भी कहता है, सुधारने की भी बात करता है। शक्ति गुमान में नहीं होती, एकमत होने से ताकत जुड़ती है और वही हमारी ताकत होती है। हम समझते हैं कि विदेश नीति की जो चुनौती आई जम्मू-कश्मीर के सिलसिले में, वह बहुत कामयाब रही है। हमको उसके लिए ऐपोलोजैटिक नहीं होना है बल्कि हमको गर्व है।

शिमला ऐग्रीमेन्ट के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ने पहले उछाला था। क्या वह सन्दर्भ नहीं रह गया है शिमला ऐग्रीमेंट का? हमने कह दिया है कि यह मत समझिए कि अगर ऐग्रीमैंट का सन्दर्भ नहीं देते तो वह एकतरफा नहीं रहेगा। आप अपने लिए भी समझ लीजिए कि शिमला ऐग्रीमैंट नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए जो आधार बना है आपस की शान्ति का, उसको उखाड़ने का प्रयास रहा है। लेकिन विभिन्न राजधानियों में यह केवल मैं नहीं कहता, इसी सरकार की सफलता रही है क्योंकि एक परम्परा एक विदेश नीति की चली आ रही है। उसका इतिहास मिल कर हमें एक सफलता देता है, लेकिन हम लोग सचेष्ट रहें और हमें सफलता मिली। इसका अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने का जो प्रयास किया गया, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली।

मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा। अन्त में इतना ही कहूंगा कि राजनीतिक परिपेक्ष्य में इस समय एक भारी राजनीतिक प्रयोग हो रहा है। एक बड़ा दल कांग्रेस रहा है और वह आजादी के बाद से रहा

है, लेकिन एक विकासशील देश जिसने नई आजादी पायी है, उसको जरूरत रही है एक स्थायित्व की। लेकिन जैसे-जैसे दशक बीतते गये सही मायने में लोगों के पास राजनीतिक विकल्प नहीं था। अगर विकल्प सही मायने में नहीं है तो जनतन्त्र बन्द हुआ। उस बन्द हुए जनतन्त्र से टूटने के कारणों और राजनीतिक विकल्प जहां हो उसको एक नये और सही अर्थों में, सही मायनों में तय कर सकें—(व्यवधान) एक सूत्रपात हुआ है। मैं सूत्रपात केवल कह रहा हूं क्योंकि अभी इस प्रक्रिया को दृढ़ होना है। इसमें अन्तरद्वंद्व हैं। हमारे अन्दर भी अन्तरद्वंद्व हैं, कॉन्ट्राडिक्शन्स हैं। उन अन्तरद्वंद्वों को भी ले करके हम हिम्मत के साथ बढ़े हैं। अभी तक स्थिति आशाजनक रही है, लेकिन हम नहीं कहते कि हम पार कर चुके हैं। हम को अभी बड़ी मंजिल पार करनी है। हम सब के ऊपर इसको पार करने की जिम्मेदारी है और जनता के लिए जिम्मेदारी है। इसी आशा को रख करके हम काम करने की कोशिश करेंगे और आपका भी इसमें सहयोग मांगेंगे। धन्यवाद।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1984 के दंगों की विधवाओं को एक हजार रुपये पेंशन देंगे। यह एक खुशी की बात है। इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। परन्तु पंजाब में जो लोग मारे गये हैं उनकी विधवाओं को भी एक हजार रुपये पेंशन देने की घोषणा करें। इससे हमें बहुत खुशी होगी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उसके बारे में बात करेंगे।

श्री राम निहोर राकेश : महोदय, इनके मुख्यमंत्रित्व काल में मुरादाबाद में जो कुछ हुआ क्या उनकी विधवाओं को भी एक हजार रुपये पेंशन दी जायेगी। —(व्यवधान) —

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनेक संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : और अधिक स्पष्टीकरण नहीं।

[हिन्दी]

अभी वक्त नहीं है। साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स लैजिस्लेटिव बिजनस शुरू हो जायेगा। ऐसी कोई परम्परा भी नहीं रही है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किये हैं। अगर कोई माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन पर अलग से सभा द्वारा मतदान कराये जाने की मांग नहीं करते हैं, तो मैं सभा के मतदान के लिए सभी संशोधनों को एक साथ रखूंगा।

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन (तिरुनेलवली) : मैं अपने संशोधन संख्या 34 को अलग से सभा के मतदान के लिए रखना चाहता हूं।